identify constraints and help the management in taking remedial measures.

(iv) Indepth critical review of the progress by the project Authorities and Administrative Ministries.

(v) Setting up of Task Force/ Empowered Committees for speedy finalisation of contract packages, solving land acquisition and other problems.

(vi) Close follow up by the Department of Programme Implementation, concerned administrative Ministries and Project authorities with the State Government, equipment suppliers, contractors, consultants and other concerned agencies to minimise delays.

(vii) Inter-ministerial coordination and interaction.

(viii) Emphasis on preparation of realistic project implementation plan.

(ix) Review by the Committee of Secretaries of the specific projects facing constraints.

Indo-Mauritius Trade

737. SHRI BHAGABAN MAJHI: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) the areas in which Indo-Mauritius trade has been established;

(b) whether Government have found new areas for the expansion of Indo-Mauritius trade relation; and

(c) if so, the details of those new areas?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): (a) to (c) It is the endeavour of the Govt. to expand trade relations with African countries including Mauritius having potential market by:—

(1) Exchange of Industry & Trade delegations;

(2) Holding of exclusive Indian Exhibitions/Fairs;

(3) Holding of periodic official level bilateral discussions to resolve bottlenecks;

(4) Holding of regional conferences of Commerical Representatives of Indian Missions to identify emerging opportunities.

As against the export turnover from India to Mauritius of Rs. 268.55 crores in 1993-94, exports from India to Mauritius during 1994-95 reached Rs 357.89 crores thus showing a rising trend.

It is primarily for the trade and business organisations of the two countries to select items for export and import from each other depending on the requirements and competitiveness of the goods. However, the main items of export from and import by india are;

EXPORT ITEMS: Cotton yarn, fabrics, Madeups; Manmade yarn, fabrics, Madeups; Manufactures of metals; Meat & preparations; Transport equipments; Plastic and Linoleum products; Natural Silk Yarn, fabrics, Madeups; marine products etc.

IMPORT ITEMS: Metalifers ores & metal scrap; Computer software; Organic chemcials; Medicinal & Pharmaceuticals Products etc.

ब्राजील से कम मूल्य पर चीनी का आयात

738. श्री सोमपाल: क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 14 जुलाई, 1995 के इकानामिक्स टाइम्स में प्रकाशित उस समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें गत वर्ष हुए चीनी आयात संबंधी घोटाले के समय

अपेक्षाकृत कम भाव पर ब्राजील से भारत में आधारित चीनी का उल्लेख किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन तथ्यों की प्रमाणिकता की जांच कराई है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) से (ग) वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार एस० टी० सी० तथा एम० एम० टी० सी० ने सरकारी खाते में जुलाई से दिसंबर 1994 के दौरान 9.77 लाख टन चीनी का सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आपूर्ति के लिए आयात किया। यह पूरी मात्रा रिफाइंड शुगर एसोशियसन (आ० एस० ए०), लन्दन के सदस्यों के साथ अनुबन्धित की गई। जहां तक "इकोनोमिक टाइम्स" जो 14 जुलाई, 1995 को प्रकाशित हुआ में छपी रिपोर्ट का संबंध है, ऐसा लगता है कि गैर आर० एस० ए० आपूर्तिकर्ता के साथ आर०एस०ए० आपूर्तिकर्ता के साथ किए गए अनुबंध की तुलना की गई है। एस० टी० सी० तथा एम० एम० टी० सी० को आर० एस० ए० सदस्यों के अलावा अन्य पार्टियों से कहीं अधिक सस्ते मूल्य के प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। तथापि सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गैर आर० एस० ए० सदस्य आपूर्तिकर्ताओं द्वारा उनके प्रस्तावों के साथ पेश की गई कीमत के 5% के बंधपत्र (बाईड बांड्स) देने अपेक्षित थे। एस० टी० सी० ने सूचित किया है कि केवल दो गैर आर० एस० ए० पार्टियों ने ऑफर भेजने के बाद निर्धारित अवधि के भीतर बंधपत्र (बाईड बांड्स) जमा कराने का प्रस्ताव रखा। इन पार्टियों को एक-एक करके आदेश दिए गए। तथापि, एक पार्टी ने निर्धारित बाईड बांड् नहीं जमा कराए तथा दूसरी भी कार्य पूरा न कर सकी।

खनिज एवं धातु व्यापार निगम लिमिटेड (एम० एम०टी० सी०) ने भी इस तरह की तीन पार्टियों को आदेश दिए जिन्होंने आर० एस० ए० सदस्यों द्वारा दिए गए मूल्यों की तुलना में कम मूल्य पर बंध पत्र (बाईड बांड्स) के साथ अपने वैध प्रस्ताव जमा कराए लेकिन इसी प्रकार से ये पार्टियां भी अनुबंध पूरा नहीं कर सकीं। एम० एम० टी० सी० तथा एस० टी० सी० ने पुष्टि की कि अक्टूबर, 1994 में मद्रास में इकोनामिक टाइम्स में जैसा प्रकाशित हुआ था कि उनका मैसर्स पैरिस की सकडैन कैरी के साथ 14000 टन ब्राजीलियन चीनी का अनुबंध किया है। वाणिज्य मंत्रालय में उपलब्ध सूचना के अनुसार एस० टी० सी० तथा एम० एम० टी० सी० ने जिन मूल्यों पर आयात किया है वे दूसरे भारतीय आयातकों के आयात मूल्यों के बराबर ही हैं।

Import of COCOA Beans

739. **SHRI V. GOPALSAMY**: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) the quantity of cocoa beans imported during the last three years, year-wise;

(b) what has been the domestic production of cocoa during this period;

(c) whether there was any gap between production and demand during this period;

(d) out of the imports, how much has been made by major multinationals, year-wise figures;

(e) whether it is a fact that Government have permitted the multinationals to import more than required to the disadvantage of farmers; and

(f) whether Government propose to curtail import of cocoa beans, if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): (a) Item 'Cocoa Beans' as such is not classified in the ITC(HS). However import of cocoa beans during the last three years had been as under:—

Year	*Quantity (Tons)*
1992-93	1243
1993-94	220
1994-95	706

Source: DGCI&S CALCUTTA.

(b) and (c) Firm production estimates of cocoa beans are available only upto 1992-93. The year-wise production of cocoa beans during the years 1990-91, 1991-92 & 1992-93 had been 6946, 7376 & 6821 tonnes respectively. While available information indicates that 1993-94 was a normal year for cocoa